ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 26-28**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

भारतीय लोक नीति प्रतिमानों का विश्लेषात्मक अध्ययन

डॉ0 पंकज तिवारी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, (म0प्र0) भारत

Received-05.07.2025, Revised-13.07.2025, Accepted-20.07.2025 E-mail : drtpankaj@gmail.com

सारांशः ***लोक नीति वह है, जो सरकारी सत्ता द्वारा समाज के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई तथा क्रियान्वित की जाती है। लोक नीति जिसे सार्वजनिक नीति भी कहते हैं और जो संस्थागत प्रस्ताव के रुप में कानूनों, विनियमों, दिशा निर्देशों और कार्यों जैसी तत्वों का एक निर्धारित समूह है। भारतीय परिपेक्ष में लोक नीति के प्रतिमानों के विश्लेषण का अध्ययन चाहे लोक कल्याण, वैज्ञानिक, व्यावसायिक उपयोगिता के कारण ही हो लेकिन इनके तत्वों का विवेचन आवश्यक है। भारतीय लोक नीति प्रतिमान के मुख्य तत्वों में नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में तार्किकता, बौद्धिकता के साथ विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक हित धारकों के बीच समन्वय स्थापित करना है। अकादमिक अवधारणा के रूप में लोक नीति समकालीन भारतीय परिपेक्ष्य में अपनी सार्थकता एवं प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं। आज भारत में लोक नीति प्रतिमान सरकार के उत्पादों की एक अध्ययन के विभिन्न शाखाओं जैसे कृषि नीति, अर्थ नीति, शिक्षा नीति, प्रबंधन नीति, व विदेश नीति के विभिन्न आयामों के रूप में प्रासंगिक बनी हुई है। वस्तुतः शासन द्वारा निर्मित वह नीति जो लोक कल्याण के लिए कार्य करती है परिणाम उन्मुख होती है और जो सदैव परिणाम की पूर्ति करती है। लोकनीति पर आधारित वह नीति जो लोक कल्याण के लिए बनाई जाती है अपनी गतिशीलता की कारण निरंतर परिवर्तित होती रहती है। भारतीय लोक नीति प्रतिमानों में नीति निर्धारण एक गतिशील प्रक्रिया है, जो वास्तव में विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक शामिल है। भारत में लोक नीति का प्रतिमान यह दर्शाता है कि एक तरफ केंद्रीय शासन नेतृत्व जो "शीर्ष से नीचे "वाले दृष्टिकोण अपनाते हैं, वहीं पर देश की संघीय ढांचा अपनी विविध आवश्यकताओं को लेकर सहयोगी, सहभागी एवं साझेदारी प्रतिमान को अपनाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ उन्मुख रहती है। भारत में लोक नीतियों के निर्माण में "शीर्ष से नीचे" वाले दृष्टिकोण को केंद्रीकृत मॉडल के नाम से जाना जाता है, इसमें भारत की संघीय सरकार नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन करते समय स्थानीय शासन एवं नागरिक समाज से सहयोग प्राप्त करते हैं। भारत में लोक नीति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिमान सहभागी मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें लोक नीति के निर्माण, क्रियान्वयन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते समय स्थानीय शासन को दृष्टिगत कार्य एवं सहयोग प्राप्त होता है ।साथ ही नागरिक समाज, मीडिया, नौकरशाही और राजनीतिक दलों का भूमिका सहयोगात्मक रहता है।***

कुंजीभूत शब्द– **लोकनीति, प्रतिमान, नागरिक समाज, नौकर शाही, तर्कसंगत प्रतिमान, संवृद्धि प्रतिमान, सहभागी मॉडल।**

प्रस्तावना – नीति को सामान्यतः एक परिवेश के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु व्यक्ति, समुदाय, संस्था एवं सरकार की निर्धारित एवं प्रस्तावित कार्य योजना के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के क्रियान्वयन के लिए नीति निर्धारण आवश्यक हो जाता है। अतः नीति संगठनात्मक लक्षणों को प्राप्त करने के लिए ढांचे का ऐसा निर्माण करती है जो लोक कल्याणकारी एवं राष्ट्रीय हित पर आधारित होता है। नीति निर्धारण सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एपल्लवी के शब्दों में" जन प्रशासन का सार नीति निर्माण है।"[1] वही मार्शल डीमॉक ने नीति की परिभाषा इस प्रकार की है "यह सचेतन रूप से स्वीकृत आचरण की संहिता है जो प्रशासनिक निर्णय का दिशा निर्देश करती है।"[2] लोक नीति सामाजिक समस्याओं को सार्थक तरीके से संबोधित करने के नियोजित एक उपकरण है। यह मुख्य रूप से कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सामाजिक कार्यों को निर्देशित करने का एक साधन है।[3] आमतौर पर लोक नीति शासको और शासितों के बीच लोकनीति के लिए विचारधारा संचालित उद्देश्यों को पूरा करने का सकारात्मक प्रयास है। इससे पता चलता है कि लोक नीति बनाने में दो महत्वपूर्ण कर्ता होते है। एक सरकार होती है जिसके पास लोक नीति निर्माण हेतु वैचारिक लक्ष्य होते हैं और दूसरी ओर विशिष्ट नीतियों और नीति प्राथमिकताओं पर पहुंचने के लिए दृष्टिकोण ।

लोक नीति शब्द को परिभाषित करने से पूर्व इसके दोनों घटको लोक और नीति स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए सार्वजनिक का अर्थ सामान्य रूप से सभी लोगों से है। नीति शब्द किसी दिए गए लक्ष्य के लिए कार्यवाही के समग्र कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। रॉबर्ट प्रेस्थास "नीति को किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किया गया विकल्प के रूप में परिभाषित करते हैं।"[4] डिमाक और डीमंक के अनुसार "नीतियां आचरण के लिए अपनाये गए वे नियम है जो की प्रशासनिक निर्णय को निर्देशित करती है।[5] वहीं डोर ने नीतियों को कार्रवाई की मुख्य रेखाओं का अनुसरण करने के लिए सामान्य निर्देश के रूप में माना है।[6] सार्वजनिक नीति वह है जो सरकारी सत्ता द्वारा अपनाई जाती है और क्रियान्वित की जाती है सार्वजनिक नीति का भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन चाहे वैज्ञानिक, राजनीतिक सामाजिक या व्यावसायिक उपयोगिता के कारण ही हो यह देखना है इनके प्रतिमानों का स्वरूप का विश्लेषण क्या है।

भारतीय लोक नीति अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वरूप में विभक्ति होती है। यह यदृशिचक आचरण की अपेक्षा परिणामोन्मुख या लक्ष्योमुख क्रियाविधि को प्राथमिकता देती है।

सकारात्मक रूप में यह सरकारी स्तर पर जन समस्याओं के प्रश्न पर किस प्रकार से करवाई शामिल हो सकती है वही नकारात्मक रूप में इसमें सरकारी मत, अभिवृत्तिया या कारवाई की अपेक्षा की जाती है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोक नीतियों का संबंध नौकरशाहो द्वारा एक निश्चित लक्ष्य एवं समय विधि के लिए जनहित में निर्णायक प्रतिमान से होता है । वस्तुतः लोक नीति अपने सकारात्मक रूप में नियम पर आधारित होती है और यह कानूनी एवं प्राधिकृत रूप से स्वीकृत होती है। यह सभी नागरिकों पर बाध्यकारी भी होती है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

भारतीय लोक नीति प्रतिमानों का विश्लेषात्मक अध्ययन करने की शैक्षिक एवं राजनीतिक दोनों ही कारण हैं। इस संदर्भ में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जटिलताओं और राज्य के लिए उनके निहितार्थों के रूप में लोक नीति प्रतिमान का अध्ययन आवश्यक है। लोक नीति के उद्देश्य के लिए नीति को पराश्रित अथवा स्वाधीन चर के रुप में देखा जा सकता है। पराश्रित चर के लिए राजनीतिक वातावरण का होना आवश्यक होता है। जो नीति निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है।

भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश शासन की अधीन आर्थिक और स्थिरता की दौड़ से गुजर रहा था। भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। दुनिया के गरीब देश में से एक भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वह किस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोक नीति का निर्माण करें । कौन सा प्रतिमान जो राष्ट्रीय हित मानव हित के लिए उपयोगी एवं सार्थक हो इस पर बल दिया गया। 1950 की दशक में यह चुनौती निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की संस्थापको, बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियो एवं समाज सुधारकों के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दी। भारत में विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद लोक नीति की बदलते रुझानों और प्रतिमानों में नेहरूवादी मिश्रित आर्थिक प्रतिमान, विकास पर आधारित उदारवादी बाजार मॉडल, पंचायती राज्य की रूप में विकेंद्रीकरण प्रतिमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोक नीति को निर्धारित निर्देशित एवं निरूपित करता है।

भारत जैसे देश में लोक नीति का निर्माण नीति निर्माता की धारणाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। भारत में विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में लोक नीति मौजूदा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर होता है। जिस वातावरण में नीति का जन्म होता है, नीति निर्माण उसी से प्रभावित होती है। लोक नीतियां भी प्राकृतिक संसाधन, भू राजनीतिक स्थिति, जलवायु और स्थलाकृति जैसी भौतिक एवं भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित होती है। रक्षा एवं विदेश नीति के लिए वातावरण मुख्यतः महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। लोक नीति के निर्माण में राजनीति शास्त्रियों द्वारा दो कारकों पर विशेष बल दिया गया है। राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक आर्थिक चर। संस्कृति जो कुछ हम सामाजिक वातावरण में रहकर आत्मसात करते हैं, उससे संबंधित होती है। संस्कृति का वह भाग राजनीतिक संस्कृति कहलाता है इसमें समाहित मूल्य, विश्वासो और अभिवृत्तियों का संबंध लोक नीतियों से होता है। सेक्लर हडसन के शब्दों में" प्रत्येक देश में नीति प्रतिपादन का निर्धारण सभी प्रकार के तरीकों से सभी प्रकार की वस्तु सामग्रियों द्वारा अनुकूलित करके किया जाता है। भारत में लोक नीति को विभिन्न प्रतिमानों और दृष्टिकोण के माध्यम से समझा जा सकता है।

तर्कसंगत नीति निर्माण प्रतिमानः नीति निर्माण का यह भारतीय प्रतिमान इस बात पर जोर देता है कि नीति निर्माण तर्कसंगत आधार पर नीति विकल्पों का एक विकल्प है। तर्कसंगत प्रतिमान जिसे शुद्ध मूल उपलब्धि को अधिकतम करने के लिए सही ढंग से डिजाइन किया गया है। यह प्रतिमान तर्कसंगत नीति का केंद्र बिंदु है, यह प्रतिमान समाज में बुद्धिबाद को आधार बनाकर सभी लोक नीति विकल्पों की खोज करने चयन करने एवं गणना करने का प्रयास करता है। अंततः ऐसी नीति का चयन करता है जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मूल्य की लागत एवं लाभ के संदर्भ में उचित हो। एक बौद्धिक तर्कसंगत उपकरण आवश्यकता पड़ने पर समाजवाद की दावे को बरकरार रखते हुए क्रांतिकारी वामपंथी से खुद को दूर करने की सुविधा प्रदान की। वस्तुतः भारत में समाजवाद को उचित ठहरना एक तर्कसंगत नीति निर्धारण के लिए आवश्यक शर्त थी। भारत में कांग्रेस की सरकार विकास की योजनाओं को समर्थन करने वाले दृष्टिकोण से सहमत थी गांधी जी के स्पष्ट कथन के विपरीत नियोजित विकास में औद्योगिकरण सहित समाजवादी साधनों में पर्याप्त रुचि दिखाई। तर्क संगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदर्श निर्णय लेने की बजाय नीति निर्माता समस्याओं की जटिलता को छोटे और समझने योग्य भागों में तोड़ देते हैं और सबसे अच्छा और संतोषजनक विकल्प चुनते हैं। अनावश्यक अनिश्चित से बचते हैं इस संदर्भ में साइमन का कहना है कि "किसी एक अलग थलग व्यक्ति के व्यवहार के लिए तर्कसंगत्ता के किसी भी उच्च स्तर तक पहुंचना असंभव है।"[7] इस प्रतिमान के उप प्रतिमानों के रूप में जन चयन प्रतिमान, उपभोग प्रतिमान एवं प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रतिमान शामिल है। लोक नीति प्रतिमान के रूप में उक्त प्रतिमानों का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रतिमान लोक नीति के संबंध में विचार करने का विशेष अलग तरीका प्रस्तुत करते हैं।

सम्वृद्धि का भारतीय प्रतिमानः भारतीय लोक नीति प्रतिमानों के रूप में इसका विशेष महत्व है यह माना जाता है कि नीति निर्माता को नीति संबंधी सीमित विकल्प ही प्राप्त होते हैं और यह अल्प परिवर्तन ही लाते हैं। यह प्रतिमान इस मान्यता पर प्रकाश डालता है कि जो संभव है वही समृद्धि दायक है, यह प्रतिमान भारतीय लोक नीति में कुछ उप प्रतिमानों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। संस्थात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत ये सरकारी संस्थाएं राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन केंद्र मानी जाती है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नौकरशाह इत्यादि शामिल होते हैं। लोक नीतियां वस्तुतः सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित, निर्धारित एवं क्रियान्वित होती है।

अभिजन का प्रतिमान – लोक नीति में श्रेष्ठ जन प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। श्रेष्ठ जन कुछ सामान्य मूल्य में विश्वास करते हैं समाज या राज्य में यह शक्ति संपन्न होने के नाते शासकीय क्रियाविधि में उनकी सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। लोक नीति निर्माण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन में अभिजन की इच्छाओं एवं मूल्यों को ही महत्व दिया जाता है। इसमें जनता सार्वजनिक नीतिगत कार्यों के प्रति उदासीन होती है। अतः श्रेष्ठ जन जनता के मत का निर्धारण करता है ।

वर्गीय प्रतिमान – भारतीय लोक नीति प्रतिमानों में अपना विशेष स्थान रखता है। लोक नीति को प्रभावित करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष का होना स्वाभाविक है। लोक नीति वर्ग संघर्ष में प्राप्त संतुलन है जो एक वर्ग की सापेक्षिक क्षमता द्वारा निर्धारित होती है इस सिद्धांत द्वारा यह माना जाता है कि जो नीति एक वर्ग के लिए उपयोगी है वही जनता के लिए उपयोगी होगी।

व्यवस्था प्रतिमान – भारतीय लोक नीति प्रतिमानो में विशेष महत्व रखता है। यह प्रतिमान सूचना सिद्धांत निवेश निर्गत और पुनर्निवेशन की प्रक्रिया पर अभिलंबित है, क्योंकि भारत एक राजनीतिक व्यवस्था है ऐसे में इस प्रतिमान का विशेष महत्व होता है। नीति चूंकि व्यवस्था का फल होती है जिसमें विविध कारकों और कर्ताओं का योग रहता है। अतः इस सिद्धांत के मान्यता के अनुसार लोक नीतियां राष्ट्र मूलक क्षेत्र मूलक, एवं स्थान मूलक होती है।[8]

समूह प्रतिमानः भारतीय लोक नीति का यह प्रतिमान प्रारंभ से ही राजनीतिक गतिविधियों के रूप में अध्ययन का केंद्र बिन्दु रहा है, लोकनीति में समूह के हित महत्वपूर्ण होते है। लोकनीति का समूह प्रतिमान राजनीति के हाइड्रोलिक सिद्धांत पर आधारित है।[9]

भारतीय लोक नीति निर्माण प्रतिमान में राज्य निर्देशित विकासात्मक संस्थाओं का विशेष महत्व होता है जनवरी 1950 में गठित योजना आयोग इसी का एक सकारात्मक रूप है।[10] जिसमें भारतीय लोक नीति की तैयारी में तीन प्रमुख सिद्धांतों को शामिल किया गया था, पहले यह था कि आजीविका के संदर्भ में पुरुषों के समान ही महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए दूसरा यह

था कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं वितरण आम जनमानस के हित में हो। तीसरा आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार से किया जाए जो सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रीय विकास के लिए सार्थक सिद्ध हो।

आर्थिक उदारीकरण मॉडल यह भारतीय लोक नीति प्रतिमान के शास्त्रीय मॉडल के रूप में जाना जाता है। भारत में 1990 में नई आर्थिक नीति कोअपनाने के साथ ही केंद्रीकृत आर्थिक विकास की ढांचे को समाप्त करने की पहल शुरु हो गई। इसमें उदारीकरण के प्रति भारतीय जनमानस की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 1991 की औद्योगिक नीति में भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण की जाल से मुक्त करने के लिए कदम उठाए गए। भूमंडलीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में बदलाव होना स्वाभाविक था। ऐसे में भारतीय लोक नीति के उदारवादी मॉडल जन कल्याण के लिए, राष्ट्रीय उत्थान के लिए और मानव हित के लिए सार्थक और उपयोगी सिद्ध हुई।

लोक नीति का विकेंद्रीकृत प्रतिमान – भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किया गया जो आमजन के लिए स्थलीय स्तर पर सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था जिसके तहत शासन व्यवस्था के 3 स्तरीय स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ। मानव और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह कदम भारतीय लोक नीति प्रतिमान के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। लोक नीति का यह भारतीय प्रतिमान भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए सार्थक सिद्ध हुआ। जिसके तहत भारत जैसे भौगोलिक विभिन्नताओं वाले राष्ट्र के लिए यह सकारात्मक कदम था। पंचायती राज व्यवस्था के साथ–साथ नगर निगमों में समावेशी विकास के लिए यह संवैधानिक परिवर्तन नागरिक समाज और राष्ट्र के लिए सार्थक सिद्ध हुआ।[11]

निष्कर्ष – उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोक नीति की बदलते प्रतिमानों का विश्लेषण किया गया इसकी शुरुआत लोक नीति के तर्कसंगत प्रतिमान एवं समृद्धि प्रतिमान के उप प्रतिमानो क्रमशः समूह प्रतिमान अभिजन प्रतिमान, वर्गीय प्रतिमान, व्यवस्था प्रतिमान के साथ–साथ नेहरु मिश्रित आर्थिक मॉडल, विकास के लिए आर्थिक उदारवादी प्रतिमान योजना आयोग का स्थान लेने वाला नीति आयोग महत्ता को समझने का प्रयास किया गया। 1990 के दशक के बाद भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के प्रभाव के कारण प्रबंधकीय लोक नीतियों का महत्व बढ़ा जिसके कारण लोक नीति के भारतीय प्रतिमानों में विकेंद्रीकृत लोक नीति प्रतिमान का महत्व बढ़ गया, फल स्वरुप स्थानीय स्वशासन के महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टिगत पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर निगम हेतु संविधान में 73वां एम 74वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान की भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व लोक नीति के आधार को रेखांकित करता है। 2015 में योजना आयोग के स्थान लेने वाला नीति आयोग लोक नीति के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अतः आज का नया भारत वैश्विक पटल पर अपनी व्यवस्थित योजनाओं, लोक कल्याणकारी नीति के कारण सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक विकास, विज्ञान एवं तकनीकी का क्षेत्र हो सभी में अपने कार्य नीतियों के कारण वैश्विक पहचान बना लिया है। भारत में लोक नीति के निर्माण में नागरिक समाज, कर्मचारी तंत्र अधिकारी तंत्र, नौकरशाह एवं मीडिया की भूमिका नि संदेह सराहनी है। अतः भारत अपनी इसी लोक नीतियों के प्रतिमानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य को समय पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेगा।

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. बासु रुमकी (1991), लोक प्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का परिचय स्टालिन पब्लिशर्स प्रा०लि०, नई दिल्ली, पृष्ठ 55.
2. वही, पृष्ठ 155.
3. Chakrabarty B. and Chand P. (2016). Public Policy Concept Theory and Practice, Sage Texts, New Delhi Page 1.
4. Ibid Page 20.
5. क्रम संख्या 1, पृष्ठ 157.
6. साइमन हर्बर्ट (1957) ऐडमिनिस्ट्रेटिव वीहेवीयर, न्यूयार्क, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 39.
7. कौर इंद्रजीत (2020) लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पेज 271.
8. Sapra Radhakrishan (2017). Public Policy A Contemporary Prospective, Sage Publication, India Pt. Ltd. New Delhi, Page 161.
9. भाम्बरी सी पी, लोक प्रशासन सिद्धांत तथा व्यवहार, जाइको पेज 198.
10. Francine R. and Frankel (2005) India's Political Economy (1947&2004), New Delhi, Oxford University Press, Page 85.
11. चक्रवर्ती एवं पांडे, भारतीय शासन एवं राजनीति पृष्ठ 262.

*****